[श्री विनायक प्रसाद यादव]

बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत इस कालाजार से हो जाएगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये, केन्द्रीय सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि यहां से डाक्टरों का एक स्पेशल जत्था वहां जाए और इसकी रोकथाम के उपाय अविलम्ब करे। इसके लिए अगर अभी से कारगर कदम नहीं उठाये गये तो विगत सत्र में जैसे तिरहुत डिविजन में हजारों आदमी कालाजार से मरे थे उसी तरह से कोसी डिविजन में भी व्यापक पैमाने पर मौतें होंगी और यह बीमारी फैलेगी। इसलिए मैं आपके जरिये से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अविलम्ब इस बीमारी को रोकने के लिए कारगर कदम उठायें।

(ii) RESTORATION OF THE MINISTRY CHARACTER OF ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): I rise to make a few submissions under Rule 377.

The Aligarh Muslim University is a great monument of the culture of the Muslims of India and was created, endowed, raised and nourished by the labour and the great sacrifices of the Muslim of India. This University is a Muslim minority institution established and administered by the Muslims. Ever since the University has been deprived of its rightful plea to the minority character there has been a growing and righteous indignation and a persistent demand for the restoration of its minority character.

The Aligarh Muslim University Amendment Act of 1972 brought about several obnoxious provisions and as a result there was a growing resentment against this amendment everywhere throughout the country. There were agitations, there were arrests and there were even Police firings.

Now, the Janata Party formed government at the Centre in the wake of great hopes and expectations that this minority character of the university would be restored; but it is with a sad heart that I have to submit that all these hopes have been belied. Nearly 8-9 months have passed and no measures have been taken in that regard. Therefore, there is not only a great resentment and restlessness among the people but there is also an imminent threat of agitation. At this juncture, I must make this strong submission both to the House and to the government that it is absolutely necessary that immediate measures should be taken to restore this minority character of the Aligarh Muslim University, to repeal the obnoxious provisions of the Amendment Act of 1972, to implement the recommendations of the Beg Committee and the Khusro Committee and to see to it that necessary protection under Articles 29 and 30 are made available to this University also. It is also necessary that the university and various other section should be taken into confidence about the measure. I hope that this matter will receive serious attention at the hands of the Government. We at least expect of this Government to make a categorical and an equivocal statement with respect to its intentions about the restoration of the minority character in order to satisfy the disturbed feeling and the minds of the minorities. We hope that necessary steps will be taken and that an immediate announcement will be made by the Government.

(iii) PREFERENCE IN EMPOYMENT TO THE PEOPLE OF CHHATISGARH AREA BY HINDUSTAN STEEL CONSTRUCTION COMPANY LTD.

श्री शरद यादव (जबलपुर) : छतीसगढ़ में हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड है। भिलाई में एक आन्दोलन पांच दस दिन से चला आ रहा है। उसकी बुनियाद बहुत पीछे पड़ चुकी थी। ये जो कारखाने खोले जाते हैं उनके पीछे एक भावना यह होती है

कि पिछड़े हुए इलाकों की बढ़ोत्तरी होगी, उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर उंचा उठेगा। जहां भिलाई कारखाना खुला है खासतौर से वहां की आबादी का चालीस फीसदी आदिवासियों का है। जो दूसरी कम्युनिटीज वहां हैं वे भी किसान और मजदूर लोग है। वहां के कारखाने में जो भी अफसर हैं वे सभी दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग हैं।

केवल मात्र पांच सैकड़ा ही स्थानीय लोगों को, लोकल—छत्तीसगढ़ के लोगों की उस कारखाने में भरती की गई है। आप देखें कि चालीस फीसदी आदिवासी हैं और उनकी जिन्दगी में जरा भी उस कारखाने से फर्क नहीं पड़ा है। यह जो असन्तोष है यह दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। इसका क्या नतीजा निकला है ? यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी राउरकेला में जो छंटनी हुई है उसमें बारह सौ मजदूर निकाल कर बाहर कर दिए गए हैं। डेढ़ बरस पहले भी इसी कारखाने में छंटनी हुई थी और उनको कहीं भी इम्प्लायमेंट नहीं दिया गया, उनको कोई वैकल्पिक नौकरी नहीं दी गई। बाकियों में से जो निकाले गए हैं उनमें से सात सौ को छत्तीसगढ़ के इस कारखाने से रख लिया गया है। इस अन्याय के खिलाफ वहां जबर्दस्त जनमत तैयार हो गया है। उसके विरुद्ध सभी पार्टियां एक हो करके आन्दोलन कर रहीं हैं, कांग्रेस के आदमी, जनता पार्टी के आदमी, कम्युनिस्ट, सी पी एम पार्टियों के आदमी मिल कर बड़े भारी पैमाने पर सभी पार्टियों के आदमी मिल कर बड़े भारी पैमाने पर आन्दोलन चला रहे हैं। उसमें नौ विधायक गिरफ्तार हुए हैं कांग्रेस सहित। इससे यह साफ हो जाता है कि यह एक जन आन्दोलन है। वहां एक एम्प्लायमेंट अधिकारी है। उसका मौसा, उसके बेटे, उसके बच्चे उसके समधी, उसके बहनोई, ये सब उस कारखाने में लगे हुए हैं। वहां पर रोजगार के दफ्तर में अस्सी हजार लोगों के नाम दर्ज हैं। केवल मात्र पांच सैकड़ा स्थानीय लोग उसमें भरती किए गए हैं। सात सौ आदमियों को ट्रांसफर करके इस कारखाने में ला कर रख लिया गया है और यह कह कर रखा गया है कि वे स्किल्ड वर्कर हैं, काम सीखे हुए लोग हैं। आई० टी० आई० या इस तरह के ट्रेनिंग स्कूलों से निकले हुए लोगों के नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं, इस तरह से 3300 लोग हैं। अभी वहां साक्षात्कार हुआ है। पांच में से दो आदमी भी नहीं लिए गए हैं। दुनिया बीसवीं सदी में से हो कर गुजर रही है लेकिन छत्तीसगढ़ और खास कर जगदलपुर चौदहवीं शताब्दी में जिन्दा है। उसको भी बीसवीं सदी में लाना आपका फर्ज है। पिछड़े इलाकों में भी स्थानीय लोगों की इन कारखानों में उपेक्षा की जाती है, रोजगार देने में पार्शलटी बरती जाती है, भेदभाव किया जाता है। अगर आपने समय रहते कदम नहीं उठाए तो उस इलाके में भारी असन्तोष व्याप्त हो जाएगा। अभी कानपुर में गोली चली थी। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मंत्री महोदय को तीन विधायकों ने लिख कर एक मैमोरेंडम भी दिया है। इस सवाल को कई बार उनके सामने रखा जा चुका है। वह बहुत व्यावहारिक आदमी हैं। इस मामले में भी मैं चाहता हूं कि वह व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं जो ज्यादती स्थानीय लोगों के साथ हुई है उसका तुरन्त निराकरण करें और जो अभी भी हो रही है, उसको समाप्त कराएं। वहां के लोगों के मन को चोट पहुंची है, दुख हुआ है और उस दुख को वह मिटाएं। जो अन्याय हो रहा है इसको मिटाएं। सात सौ लोगों को वहां पहुंचाया गया है, उनको तत्काल वापिस भेज दिया जाएगा यह आश्वासन वह हमें दें ताकि वहां जो आन्दोलन चल रहा है वह शान्त हो सके, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और उनका पिछडापन दूर हो सके।

[श्री शरद द दवे]

अगर आपने दूसरे प्रदेशों के लोगों को वहां भेजना जारी रखा तो इससे लोगों के मन में जलन पैदा होगी, आपसी वैमनस्य बढ़ेगा। इस वैमनस्य को भी रोका जाना चाहिए।

हमारा कहना यह नहीं है कि दूसरे प्रान्तों के लोगों को कहीं रोजगार न मिले लेकिन कम से कम कोई निश्चित सीमा तो हो। 50 प्रतिशत स्थानीय आदमियों को रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय कुछ बातें कहें तो अच्छा रहेगा।

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): Sir, I have listened to the hon. Member. Certain corrections are required. That is why I have to stand up to speak on his observations.

A steel plant anywhere in India is a steel plant; any major national project is a national project. To say that only local people are employed in a major undertaking....

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayn-kil): Sir, I rise on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will please take your seat. There is no point of order. If a Minister wants to say anything on 377, he can say so. I know the procedure having been here for so many years. I know what goes on here.

SHRI VAYALAR RAVI: You will kindly see the rules. If the Minister wants to make a statement, he should give a copy of it in advance. Then only he may make a statement.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ravi, you are absolutely mistaken. Under Rule 377, a Member makes a mention and, if the Minister feels, that he should reply, he can do so with the permission of the Chair. I have given him the permission.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, in the Fifth Lok Sabha, there was a ruling given in this House by the Speaker, Shri Sanjiva Reddy. He has given his ruling in this House if I remember correctly on the point of Shri Shyamnandan Mishra.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ravi, I think you are not remembering it correctly. I rule that there is no point of order. You will please sit down.

SHRI VAYALAR RAVI: My point of order is this. There is a ruling given by Shri Sanjiva Reddy, former Speaker in this hon. House. According to that, if the Minister wants to make a statement on the floor of the House, there is a specific mention that the Minister concerned must give a notice.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ravi please do not try to confuse the statement which the Minister wants to make *suo motu* and his reply to the point raised by the hon. Member under 377. I know that. You carry on, Mr. Patnaik.

SHRI VAYALAR RAVI: He must give a prior notice for it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ravi, I am very sorry there is no point of order. Perhaps you have not gone through the proceedings correctly. You will please go through them.

SHRI VAYALAR RAVI: I am sorry, Sir, you are mistaken on the ruling. Under Rule 377, if the minister wants to make a statement....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ravi, the matter has just been raised under 377. Some hon. Member made certain points. And, if the minister wants to reply to them, he can do so. There ends the matter. This is the ruling from the Chair.

SHRI VAYALAR RAVI: That is not a correct ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister may now go ahead with his reply.

SHRI BIJU PATNAIK: Sir, this is a construction company owned by the Government of India which employs people—skilled, unskilled, engineers and technicians from various parts of the country. As I said it is a construction company and, as the work finishes, from one area, these people are moved to different areas of the country or, even, sometime, outside the country when there is a foreign contract.

At the moment, at Bokaro, the work has been substantially reduced and there are 7500 employees who are surplus at Bokaro. The company's attempt is to disperse these surplus employees to different parts of the country and, in fact, they have been sent out to different States in this country. While the Bhilai expansion scheme is now going to take place, semi skilled workers are being transferred to Bhilai. Sir, I have written a letter to the local M.P. and the words which have been used in that letter are:

> "For the expansion of Bhilai Steel Plant, I have no doubt, local people of Chhattisgarh will receive due consideration."

I have been informed that nearly 20,000 workmen would be required to undertake the job of Bhilai expansion and out of the 7,500 surplus men from Bokaro probably 1,500 to 2,000 will be available for Bhilai who have done same work at Bokaro and are used to the type of work. They are skilled and semi-skilled workers.

श्री मदन तिवारी (राजनंदगांव) : भिलाई में भी बहुत लोग हैं।

SHRI BIJU PATNAIK: In Bhilai also for the same reason that we want more men the HSCL had taken interviews. I have instructed that suitable men from those people interviewed to the extent of 1,000 or 1,500 workmen should be taken by HSCL immediately.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : मगर उसी तरह के आदमी भिलाई में मौजूद हैं। यह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां स्किल्ड वर्कर्स हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी जो आप कह रहे हैं, श्री शरद यादव ने भी कहा है।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मध्य-प्रदेश के लोगों को कभी दूसरी जगह काम नहीं मिला।

SHRI BIJU PATNAIK: Does the hon'ble Member want me to dismiss 7,500 people of Bihar? I request the hon'ble Members to think of this country as a whole and not Chhattisgarh alone. The local peoples' interest will not be forgone by HSCL. This is only a construction job. In another three years time this construction work will be over. Now, after three years when there is no job and if I want to transfer them to Bihar and Biharis create this problem what will happen to the people of Chhattisgarh. I wish to emphatically state—as I have already made a commitment here in this respect—that we are going to take a large number of local people for this job. Only a small portion out of 7,500 will go to Bhilai. It will be unfortunate if we start State war on this basis. There are at least one lakh people of Chhattisgarh who work in Orissa and many people in Orissa do not have job. I am very sorry to say this but I shall do justice. I shall go out of my way to take them maximum number of people from that area. It is unfortunate if the local labour exchange creates subterfuge and does not put on the list of employment exchange roster

[Shri Biju Patnaik]

the Chhattisgarh people. That is not my fault. Hon. Members should take it up with the M.P. government. I am sending the secretary of the Steel ministry within a week there to sort out this problem. I am equally anxious as my colleagues here to see that the local people, poor people not only get employment but they get it all around. I have ordered the steel authorities to adopt villages around the steel plant and to give them help. They are poor people I have ordered that the local school, women's college, hospitals, etc., should be assisted by the steel authority and the steel plants I have informed Shri Mohan Bhaiya, M.P. in the form of a letter; this is a commitment of the government and I am making the same commitment here. But if local pasions are roused, I should like to caution them in this House that the same passion can be aroused ten times over from other parts of the country. This must not happened; this should not happen. This happened in Bombay some time back when Shiv Sena started an agitation.

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात ही नहीं कही। मैंने कहा कि कुछ लिमिटेशन रखिए।

SHRI BIJU PATNAIK: For one man from outside, you will have three men. If you are satisfied at 50:50, you should be satisfied with this. I hope I have explained the position to the hon. Members' satisfaction.

श्री एच० एल० पटवारी : (मंगलदाई) मेरा प्वांइट आफ आर्डर है। आज की कार्य सूची में छठें नम्बर पर प्राथमिक अध्यापकों की पेटीशन है जिस में मेरा नाम था। वह पेटीशन मेरे पास है। वह पेटीशन पेश नहीं की गई है। उस समय 1 बज गया था...

उपाध्यक्ष महोदय : पेटीशन तो हाउस में प्रेजेन्ट हो गया।

श्री एच० एल० पटवारी : नहीं हुआ। पेटीशन हमारे पास है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिलीप चक्रवर्ती ने उसे प्रेजेन्ट कर दिया है।

श्री एच० एल० पटवारी : नहीं, वह प्रेजन्ट नहीं हुआ। वह पेटीशन हमारे पास है। दो लाख अध्यापक यहां आए...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Dilip Chakravarty's name was also there and the petition had been presented.

श्री एच० एल० पटवारी : मगर वह पेटीशन दाखिल नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : दाखिल हो गया है।

श्री एच० एल० पटवारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यापकों का मामला है। हमको अभिशाप हो जाएगा... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have said enough. I am telling you that the petition had been presented. If you insist on continuing like this whatever you say will go off the record.

14.33 hrs.

COMPANIES (AMENDMENT) BILL
—contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up further discussion of the Companies (Amendment) Bill.

SHRI R. VENKATRAMAN (Madras South): Yesterday, I was dealing with clause 5 of the Bill which refers to section 220 of the Indian Companies Act. I was pointing out that under section 219 of the Indian Companies Act a shareholder was entitled to receive a copy of the balance sheet as well as the profit and loss account before the annual general meeting. If the annual general meeting is not